बिहार विधान परिषद्

187वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 4

9 अग्रहायण, 1939 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------

30 नवम्बर, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 20

1.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	02
2.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	02
3.	परिवहन विभाग	....	....	02
4.	जल संसाधन विभाग	....	....	05
5.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	....	....	01
6.	वित्त विभाग	....	....	01
7.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	02
8.	समाज कल्याण विभाग	....	....	01
9.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	01
10.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	02
11.	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**20**

निगरानी कमिटी का गठन

***** 39. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के बेरोजगार युवा-युवतियों को केन्द्र और राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन बेरोजगारों को समय पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से यह योजना कुंठित हो जा रही है और बेरोजगार लाभुक हताश हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता का नियमित भुगतान करने एवं इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए वार्ड स्तर पर निगरानी कमिटी का गठन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पॉलिथीन बैगों पर रोक

***** 40. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में व्यापक रूप में पॉलिथीन बैग के चलन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा शहरों एवं कस्बों के नाले भी सही रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में पॉलिथीन बैग पर अविलंब रोक लगाने हेतु क्या विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कबतक

***** 41. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि एक ही छत के नीचे परिवहन विभाग की सभी सुविधाएं देने के लिए पटना सहित 10 जिलों में यह काम जमीन के अभाव में बंद है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कार्य से सभी जिलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एवं डी.टी.ओ. कार्यालय-सह सुविधा केन्द्र बन जाने से लोगों को एक जगह कार्य कराने में आसानी होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित कर अविलंब जमीन उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

आड़ का निर्माण

***** 42. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले की बागमती नदी के दक्षिण किनारे पर बने तटबंध में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रेलवे लाइन के जनाढ़ पुल से लेकर आगे पूरब 10 कि.मी. तक प्रावधान के अनुसार Borrowpits में हर 100 फीट की दूरी पर 20 फीट का आड़ छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उसके रख-रखाव के अभाव में आड़ जीर्ण-शीर्ण हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रावधान के अनुसार आड़ का निर्माण कबतक करना चाहती है ?

ठोस कार्रवाई

***** 43. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद पटना शहर में शराब तस्करों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से होम डिलीवरी कर शराब उपलब्ध करायी जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे शराब तस्करों के विरुद्ध कौन-सी ठोस कार्रवाई कर शराब की उपलब्धता को रोकना चाहती है ?

योगदान कबतक

***** 44. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त अंकेक्षण विभाग के राजीव रंजन गुप्ता, वरीय अंकेक्षक-2 को बिहार सरकार के द्वारा विरमित किये जाने के उपरांत 9.1.2017 को मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, योजना-सह-वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखंड, रांची में योगदान समर्पित किया गया, परन्तु झारखंड सरकार के सम्यक विचारोपरांत राजीव रंजन गुप्ता का योगदान अस्वीकृत कर बिहार राज्य सरकार को वापस पत्रांक-का.आ.सं.-38 वि.अ. (1) व.-01/17/22/वि.अ. रांची दिनांक-19.4.2017 के द्वारा कर दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राजीव रंजन गुप्ता, वरीय अंकेक्षक-2, जो विगत लगभग 4 माह से योगदान एवं वेतन की प्रक्रिया में मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको सरकार कबतक योगदान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

विशेष प्रयास

***** 45. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यलय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के परिसर में पुराने एवं बहुमूल्य पेड़ों की बहुतायत है जिन्हें महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह एवं कामेश्वर सिंह के प्रयासों से लगाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इन पेड़ों को धड़ल्ले से काटकर नष्ट किया जा रहा है परन्तु वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि इस परिसर में अवस्थित पेड़ों का सर्वेक्षण करने, इसकी सुरक्षा करने एवं इसे बचाने के विशेष उपाय करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों सहित देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिच्यूट से भी अनुरोध किया गया था परन्तु इसका कोई फलाफल नहीं निकला;

(घ) क्या यह सही है कि अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ों को रोकने के लिए भी वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस परिसर में खड़े अनमोल पेड़ों को बचाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बस सेवा

***** 46. **श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भितिहरवा में स्थापित आश्रम अब संग्रहालय के रूप में है और इसे देखने के लिए पूरे बिहार राज्य एवं देश के कोने-कोने से लोग आते हैं परन्तु पटना से सीधी डिलक्स बस सेवा नहीं रहने के कारण उन्हें कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना से भितिहरवा के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है परन्तु परिवहन विभाग के पदाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो महात्मा गांधी के चंपारण शताब्दी वर्ष में क्या सरकार पटना से भितिहरवा तक सीधी बस सेवा शुरू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जानमाल की सुरक्षा

***** 47. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि उत्तर बिहार में बाढ़ की आपदा से भारी जनधन की क्षति होती है एवं अरबों की फसल बर्बाद होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाढ़ के स्थायी समाधान की दिशा में कोई प्रयास करना चाहती है, ताकि जान-माल और फसल की सुरक्षा हो सके, यदि हां तो कबतक ?

चेक डैम का निर्माण

***** 48. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिल के इमामगंज प्रखंड अन्तर्गत पननियां, नगवां एवं चुआवार पंचायतों की लगभग तीन हजार (3000) एकड़ जमीन हेतु किसानों के पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों के हित में सिंचाई हेतु उक्त पंचायत अन्तर्गत भलुआही पहाड़ एवं सीताहीं पहाड़ के बीच चेक डैम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नहर का आधुनिकीकरण

***** 49. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला और बक्सर जिला की सोन नहर का आधुनिकीकरण नहीं होने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है;

(ख) क्या यह सही है कि नहर और शाखाओं में मिट्टी, पेड़, पौधे भर गए हैं, कई जगह नहर टूट गयी है, दोनों तरफ बैंक भी काफी कमजोर हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण किसानों की फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सोन नहर का आधुनिकीकरण (पक्कीकरण) कराना चाहती है ?

प्रोन्नति कबतक

***** 50. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ज्ञापांक-3317/पी.-2, दिनांक-3.9.2010 ई. को ए.एस.आई. की एस.आई में प्रोन्नति दी गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि एस.आई. से इन्सपेक्टर में ज्ञापांक-17/324 पी.-01, दिनांक-30.8.2017 द्वारा प्रोन्नति दी गयी जबकि 31.12.1981 तक प्रोन्नति दी जानी थी;

(ग) क्या यह सही है कि 1994 बैच के सीधे नियुक्त अवर निरीक्षकों को प्रोन्नति दे दी गई है, परन्तु विभागीय प्रोन्नत अवर निरीक्षकों को इस प्रोन्नति से अबतक वंचित रखा गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 31.12.1981 तक वरीययता सूची के आधार पर एस.आई. से इन्सपेक्टर के पद पर प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दाहा नदी की सफाई

***** 51. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड के सिसवां भोजछापर से निकल कर सासामुसा होते हुए सीवान-छपरा की तरफ जाने वाली दाहा नदी की स्थिति अत्यंत दयनीय है;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ के दिनों में दाहा नदी दियारा क्षेत्र के अधिक जल जमाव की निकासी के साथ सिंचाई का भी मुख्य कार्य करती है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से उक्त नदी का सफाई कार्य नहीं कराया गया है जिससे नदी पानी का बहाव सुचारु रूप से नहीं कर पाती है और आसपास के क्षेत्रों में भारी फसल नुकसान कराती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दाहा नदी की सफाई पर कबतक विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वृद्धा पेंशन का भुगतान

***** 52. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड अंतर्गत योगिया ग्राम निवासी मोसमात सुजान देवी की वृद्धा पेंशन विभागीय उदासीनता के कारण नवम्बर, 2011 से अबतक लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में मोसमात सुजान देवी ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनिया को इस आशय की लिखित जानकारी दी थी;

(ग) क्या यह सही है कि पीड़िता ने दिनांक 31.1.2017 को वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनिया को सम्पूर्ण कागजात के साथ लिखित रूप से वस्तुस्थिति से अवगत कराया था;

(घ) क्या यह सही है कि पीड़िता ने थक-हारकर दिनांक-6.2.2017 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जयनगर के यहां याचिका प्रस्तुत की और आदेश संख्या-50511-01976, दिनांक-20.4.2017 को पीड़िता को लंबित वृद्धा पेंशन की राशि एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया, परन्तु वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर की हठधर्मिता के कारण पीड़िता को आजतक लंबित वृद्धा पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोसमात सुजान देवी की लंबित वृद्धा पेंशन की राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वाहनों की नीलामी

***** 53. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य के थाना में जब्त की गई बेकार पड़ी हुई गाड़ियां सड़ रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जब्त किए गय वाहनों की नीलामी नहीं होने से उक्त सभी वाहन थाना परिसर के बाहर रखे गये हैं जिससे उक्त परिसर में गंदगी बनी रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना जिले के पत्रकार नगर थाना द्वारा जब्त किये गये वाहन सड़क किनारे रखने से प्राय: जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आने-जाने वाले वाहनों को काफी मशक्कत कर रास्ता पार करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थाने में जब्त किये गये वाहनों की नीलामी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अनुशासनात्मक कार्रवाई

***** 54. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला के प्रखंड प्रमुख, कहलगांव द्वारा दिनांक-20.9.2017 को थाना कांड संख्या-514/17 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहलगांव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित तिथि को ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहलगांव द्वारा थाना कांड सं.-513/17 में प्रखंड प्रमुख, कहलगांव के पति एवं छः अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड प्रमुख, कहलगांव द्वारा पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराने थाना गई किन्तु उनकी प्राथमिकी को दर्ज नहीं किया गया बल्कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्राथमिकी के बाद ही उनकी प्राथमिकी को दर्ज किया गया;

(घ) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, कहलगांव द्वारा प्रखंड प्रमुख, कहलगांव के साथ मारपीट की गई तथा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, साथ ही फर्जी प्राथमिकी को सही ठहराकर फर्जी प्राथमिकी को वरीयता दी गई जबकि सत्य घटना की प्राथमिकी को दूसरे दरजे का वाद बनाया गया;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फर्जी प्राथमिकी दर्ज कर प्रखंड प्रमुख, कहलगांव के पति को जेल भेजने वाले पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक तथा प्रखंड प्रमुख, कहलगांव के साथ मारपीट करने वाली तथा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समय निर्धारित

***** 55. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 1063 प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) में करीब 400 से ज्यादा संस्थान या तो फर्जी हैं अथवा मानकों के अनुसार खरेनहीं उतरते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसकी जांच हेतु चार टीमों का गठन किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि जिन संस्थानों में उपकरण तो दूर आवश्यक भवन एवं कक्षाएं भी नहीं हैं, एसबेस्टस वाले एक-दो कमरों में ही कई ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वैसे संस्थानों को भी कागज पर सही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी संस्थानों की सम्यक जांच हेतु समय निर्धारित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

चेक डैम बनाने पर विचार

***** 56. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड की बदुआ नदी में गोड़ा लखनपुर के निकट एक चेक डैम बनने से 1700 सौ एकड़ जमीन की सिंचाई से किसानों को लाभ होगा;

(ख) क्या यह सही है कि प्रधान सचिव, लघु सिंचाई विभाग के यहां किसानों ने मिलकर आवेदन दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अभी तक किसानों के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा कराने की दिशा में चेक डैम बनाने की कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्टेट बोरिंग चालू कबतक

***** 57. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत बनियापुर प्रखंड के लौवां कला गांव में सिंचाई हेतु वर्ष 2007 में स्टेट बोरिंग अधिष्ठापित किया गया था, जो अधिष्ठापन के समय से ही खराब पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि स्टेट बोरिंग खराब होने के कारण सिंचाई व्यवस्था चौपट हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब पड़े स्टेट बोरिंग को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रोत्साहन राशि

***** 58. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के दसवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती आ रही है, परन्तु दो सालों से यह व्यवस्था बंद पड़ी है,

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के दसवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था पुन: चालू करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 30 नवम्बर, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्